



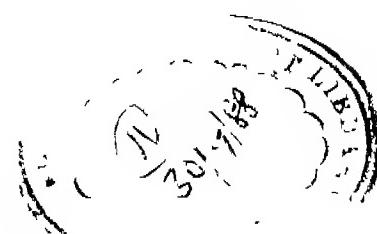
भारत का राजापत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—संख्या 3—उप-लाइ (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 60]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 1988/माघ 15, 1909

No. 60]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 1988/MAGHA 15, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाले जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विन मतालय
(राजस्व विभाग)
(विदेशी कर प्रभाग)
नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1988

अधिसूचना
आयकर

सा. का. नि. 77 (अ) —आय पर कर की बाबत दोहरे कराधान से बचने और राज वित्तीय अपवचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और हण्डोनेशिया गणराज्य की सरकार के बीच इससे मंत्रभन करार, 19 दिसम्बर, 1987 को, दोनों सभिदाकारी राज्यों द्वारा उनकी विधियों के अधीन अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा हो जाने के बारे में, उक्त करार के अनुच्छेद 28 द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में एक दसरे को अधिमूचित किए जाने पर, प्रवृत्त हुआ है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) अनिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंधों को भारत सरकार में कार्यान्वयन किया जाए।

उपायन

आय पर करों के मवध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और हण्डोनेशिया गणराज्य के बीच करार आय पर करों के मवध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और हण्डोनेशिया गणराज्य के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और इण्डोनेशिया गणराज्य की सरकार ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए करार निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार सहमति घोषित की है:

अनुच्छेद 1

व्यक्तिगत विषय-क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

करार के अन्तर्गत आने वाले कर

1. जिन करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं:

(क) भारत में :

- (i) आयकर जिसमें उस पर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत लगाया गया कोई भी अधिभार शामिल है;
- (ii) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अन्तर्गत लगाया गया अतिकर;

(एतदपश्चात् “भारतीय कर” के रूप में उल्लिखित)।

(ख) इण्डोनेशिया में :

अनडांग-अमडांग पाजाक पेंगासिलन 1984 (1983 का कानून संख्या 7) के अन्तर्गत लगाया गया आयकर तथा उस हृद तक जहाँ तक ऐसे आयकर कानून में व्यवस्था की गयी है अडोनिसी पाजाक पसरोअन 1925 (1925 का सरकारी राजपत्र संख्या 319 जिसे 1970 के कानून संख्या 8 द्वारा अन्तिम बार संशोधित किया गया था) के अध्यधीन लगाया गया कम्पनी कर तथा अनडांग-अमडांग पाजाक अटास बूंगा, डिवीडेन जान रायल्टी 1970 (1970 का कानून संख्या 10) के अध्यधीन लगाया गया कर;

(एतदपश्चात् “इण्डोनेशिया कर” के रूप में उल्लिखित)

2. यह करार, किसी भी समरूप अथवा सारतः उससे भिनते-जुलते करों पर भी लागू होगा जो बतौमान करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख के बाद, पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर, दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य द्वारा लगाए जायेंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सूचना एक-दूसरे को देंगे।

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार में, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) “भारत” शब्द से अभिप्रेत है—भारत का क्षेत्र और उसमें प्रादेशिक समुद्र और उसके ऊपर का आकाशीय क्षेत्र और साथ-ही-साथ अन्य कोई भी समुद्री क्षेत्र शामिल है जिस पर भारतीय कानून के अनुसार तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार विशेषकर सागर विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र अधिसमय, 1982 के अनुसार भारत की प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं।

(ख) “इण्डोनेशिया” शब्द से अभिप्रेत है—इण्डोनेशिया गणराज्य के कानूनों में यथापरिभाषित उसका क्षेत्र तथा निकटवर्ती ऐसे क्षेत्र जिन पर अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, विशेषकर सागर विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र अधिसमय, 1982 के उपबंधों के अनुसार इण्डोनेशिया गणराज्य की प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार अथवा अन्य अधिकार हैं।

(ग) “एक संविदाकारी राज्य” और “दूसरा संविदाकारी राज्य” शब्दों से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा इण्डोनेशिया अभिप्रेत है;

(घ) “कर” शब्द से विषयगत पाठ की अपेक्षानुसार भारतीय कर अथवा इण्डोनेशियाई कर अभिप्रेत हैं, परन्तु इसमें ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी चूक अथवा भूल के सन्दर्भ में देय हो जिन पर यह करार लागू होता हो अथवा जो उन करों के संबंध में लगाया गया कोई अर्थ-दण्ड हो;

(ङ) “व्यक्ति” शब्द में कोई व्याटि, कोई कम्पनी, तथा कोई अन्य सक्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अन्तर्गत एक कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में मानी गयी हो;

(च) “कम्पनी” शब्द से ऐसा कोई भी निगमित निकाय अथवा ऐसी कोई भी सक्ता अभिप्रेत है जो मंबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अन्तर्गत एक कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में मानी गयी हो;

(छ) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम” तथा “दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम” शब्दों से श्रमशः एक संविदाकारी राज्य के विसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) “अन्तरराष्ट्रीय यातायात” शब्दों से अभिप्रेत है—

एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित किसी जलयान अथवा किसी वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन, सिवाय इसके जब उक्त जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थान के बीच ही चलाया जाता हो;

(क्ष) “सक्षम प्राधिकारी” शब्द से अभिप्रेत है—भारत के भागों में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि तथा इण्डोनेशिया के भागों में, वित्त मंत्रालय अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ञ) “राष्ट्रिक” शब्द से अभिप्रेत है—किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता रखने वाला कोई भी व्यष्टि और कोई भी विधिक व्यक्ति, भागीदार अथवा एसोसिएशन जिसे संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से अपनी हैंसियत प्राप्त हो।

2. जहां तक एक संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार को लागू करने का संबंध है, किसी भी शब्द का, जो इस करार में परिभाषित नहीं है, विषयगत पाठ की अन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर, वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन कानूनों के अधीन उसका अर्थ होता है। जो उन करों से संबंधित है, जिन पर यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए “एक संविदाकारी राज्य का निवासी” शब्दों में ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत, उसके अधिकारास; निवास, प्रबन्ध-स्थान अथवा इसी प्रकार की विस्तीर्ण के कारण उसमें कर लग सकता है। विन्तु इन शब्दों के अर्थ-विस्तार के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता है जिस पर उस राज्य में स्रोतों से प्राप्त आय के मंबंध में ही उस राज्य में कर लग सकता है।

2. जहां पंरामाफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यष्टि दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो उसकी हैंसियत निम्नानुसार निश्चित की जाएगी;

(क) वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उमको कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो; यदि उमको दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके माध्यम से उसके अधिकारान और अधिकारी संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र);

(ख) यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा उमको दोनों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका ऐसा आवास हो जिसमें वह सामान्यतः रहता हो;

(ग) यदि उसका दोनों राज्यों में ऐसा आवास हो जिसमें वह सामान्यतः रहता हो अथवा दोनों में से किसी में भी ऐसा आवास नहीं हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहां पंरामाफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यक्ति में भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, उसके नियामीकरण के रथान, प्रभावी प्रबन्ध-अधिकार के स्थान तथा अन्य संगठन कारकों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रश्न का निर्णय परस्पर सहमति से करेंगे।

अनुच्छेद 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, “स्थायी संस्थापन” शब्दों से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जिसके माध्यम से किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. “स्थायी संस्थापन” शब्दों के अर्थ-विस्तार के अन्तर्गत विशेषतः निम्नलिखित आते हैं।

(क) प्रबन्ध-अधिकार का कोई स्थान;

(ख) कोई शाखा;

(ग) कोई कार्यालयः

(घ) कोई कारखाना;

(ङ.) कोई कंपनीशाला;

(च) कोई आन, कोइ तेल प्रथवा गैस कूप, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निकरण का कोई अन्य स्थान;

(छ) कोई भवन-स्थल अथवा कोई निर्माण अथवा प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उसके संबंध में पर्यवेक्षी कार्यकलाप, लेकिन केवल ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप जो 183 दिन से अधिक अवधि के लिए जारी रहता हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, “स्थायी सम्पादन” शब्दों के अर्थनियतार के अन्तर्गत निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा।

- (क) अनन्य स्पष्ट में उद्यम के माल अथवा निजारती सामान के भण्डारण अथवा उसके प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयाग करना,
- (ख) केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा निजारती सामान का कोई स्टाक रखना,
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल समाधित किए जाने के उद्देश्य से उद्यम के माल अथवा निजारती सामान का कोई स्टाक रखना,
- (घ) उद्यम के लिए केवल माल अथवा निजारती सामान खरीदने अथवा सूचना एकत्र करने के उद्देश्य से कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना,
- (इ) उद्यम के लिए केवल विज्ञापन के प्रयोजनार्थ, सूचना देने के लिए, वैज्ञानिक अनुमधान के लिए अथवा समान कार्यकलापों के लिए, जो प्रार्थक अथवा सहायक किस्म के हों, कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना।

4. जहा कोई व्यक्ति (किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी एजेंट से भिन्न व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 7 के उपबंध लागू होते हो) दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर में एक सविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा हो, तो किन्हीं भी कार्यकलापों के बारे में, जो वह व्यक्ति उस उद्यम के लिए सम्पन्न करता है, उस उद्यम का प्रथमोलिंग्वित राज्य में कोई स्थायी सम्पादन होना माना जाएगा, यदि

- (क) वह व्यक्ति, उद्यम की तरफ से सविदाकारी नियमित करने के लिए प्रथमोक्त राज्य में व्यावहारिक स्पष्ट से प्राधिकार रखता हा, अथवा
- (ख) वह व्यक्ति प्रथमोक्त सविदाकारी राज्य में उद्यम के माल अथवा पृथ्ये वस्तुओं का ऐसा स्टाक रखता हो, जिससे वह उस उद्यम की तरफ से नियमित स्पष्ट से माल अथवा पृथ्ये वस्तुओं की डिलीवरी करता है।

5. एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के बारे में दूसरे सविदाकारी राज्य में एक स्थायी सम्पादन का होना उस स्थिति में माना जाएगा यदि वह राज्य दूसरे सविदाकारी राज्य में, अपने कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के भाध्यम से जो किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी अभिकर्ता से भिन्न हो और जिस पर पैराग्राफ 7 के उपबंध लागू होते हो, परामर्शदात्री भेवाओं सहित स्वाएं प्रवान करना हा, वशतें कि उस प्रकार के कार्यकलाप देश के भीतर (भारत अथवा नगरद्वंद परियोजना के लिए) किन्हीं भी बारह महीने की अवधि में

कुल मिलाकर 91 दिन की अवधि अथवा अवधियों के लिए किए जाने रहते हो।

6. एक सविदाकारी राज्य के किसी बीमा उपबंध के मबद्दल में उस स्थिति को छोड़कर जब वह पुनर्बीमा में सम्बद्धित हो, यह माना जाएगा कि उसका दूसरे सविदाकारी राज्य में एक स्थायी सम्पादन है, यदि वह दूसरे राज्य में प्रीमियम एकत्रित करता है अथवा किसी ऐसे कर्मचारी या किसी ऐसे प्रतिनिधि के माध्यम से, जो पराग्राफ 7 के अर्थ के अन्तर्गत एक स्वतंत्र हैसियत का आभिकर्ता नहीं हो, वह स्थित जोखिम का बीमा करता हो।

7. एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे सविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण में कोई स्थायी सम्पादन नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कर्मीशत एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम ने कारोबार करता है, वशतें कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार को सामान्य स्पष्ट से कर रहे हो। तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णत अथवा लगभग पूर्णत उस उद्यम की एवज में समर्पित हो, तो वह ऐसे पैराग्राफ के अर्थ के प्रतिमार एक स्वतंत्र हैसियत वाला एजेंट नहीं माना जाएगा।

8. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी, जो एक सविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियन्त्रण करती है अथवा उसके द्वारा नियन्त्रित होती है जो दूसरे सविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा जो उस दूसरे सविदाकारी राज्य (चाहे किसी स्थायी सम्पादन के माध्यम से अथवा अन्यथा) में कारोबार चलाती है, तो उस दोनों कम्पनियों में में कोई भी कम्पनी स्वत दूसरी कम्पनी का एक स्थायी सम्पादन नहीं बन जाएगी।

अनुच्छेद 6

अचल सम्पत्ति में आय

1. एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति में प्राप्त आय पर, जिसमें कृषि अथवा बानिकी से प्राप्त आय भी शामिल है, उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. “अचल सम्पत्ति” शब्द का अर्थ निम्नपर उस सविदा कारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत होगा जिसमें प्रणालीन सम्पत्ति स्थित है। इन शब्दों में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के उप माध्यन के स्पष्ट में सम्पत्ति, कृषि एवं बानिकी में प्रयुक्त पण्डित और उपस्कर तथा ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानूनों के उपबंध लागू होते हो, अचल सम्पत्ति का भोगने का अधिकार, तथा खानिज भण्डार, स्त्रात तथा अन्य प्राकृतिक समाधनों के कार्य अथवा कार्य करने के अधिकार के लिए प्रतिकल के स्पष्ट में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार। जापातो, नाबो तथा वायुयानों को ग्रचल सम्पत्ति नहीं माना जाएगा।

३ पैराग्राफ १ के उपबंध अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग से, किसी पर देने से श्रवण किसी अन्य प्रकार में उपयोग में प्राप्त होने वाली श्राय पर भी लागू होंगे।

४ पैराग्राफ १ और ३ के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति में प्राप्त श्राय के साथ-साथ स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिये इस्तेमाल में लायी गयी अचल सम्पत्ति से प्राप्त श्राय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद ७

कारोबार से लाभ

१ किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर उसी राज्य में कर केवल तभी लगाया जाएगा जब कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि वह उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो निम्ननिर्धित के कारण उत्पन्न हुआ भाना जा सकता है—(क) उस स्थायी संस्थापन, (ख) उस दूसरे राज्य में एक समान श्रवण उससे मिलते-जुलते मान श्रवण पर्यावरण-वस्तुओं की बिक्री जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती है।

२. पैराग्राफ ३ के उपबंधों के रहने हुए जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जरिए वह पर कारोबार करता हो, वहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा जो उसको प्राप्त होने की तब श्रेष्ठता रहती जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और निश्चित श्रेष्ठ उद्यम होता और उस उद्यम के माथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।

३. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उन व्ययों को कटौतियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा, जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ किए गए हो, जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल है, चाहे वह उस राज्य में किए गए हों जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित है श्रवण अन्यत्र किए गए हों। किन्तु उक्त स्थायी संस्थापन द्वारा उस उद्यम के प्रधान कार्यालय को श्रवण उसके अन्य कार्यालयों से से किसी कार्यालय को पेटेन्टो श्रवण अन्य अधिकारों के उपयोग के प्रतिक्रिया में रायलिंगों, फीस श्रवण अन्य मिलती-जुलती श्रदायगियों के तीर पर, श्रवण की गयी विशिष्ट सेवाओं श्रवण प्रबन्ध व्यवस्था के निए कमीशन के तीर पर श्रवण किसी वैक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के स्वयं में यदि कोई रकमें

श्रदा की गयी हों (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) तो उनके संबंध में ऐसी किसी कटौती की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार, किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उन रकमों को हिसाब में नहीं लिया जायेगा, जो स्थायी संस्थापन द्वारा उस उद्यम के प्रधान कार्यालय को या उसके अन्य कार्यालयों में में किसी कार्यालय को पेटेन्टो श्रवण अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले में रायलिंगों, फीस श्रवण ऐसी ही अन्य अदायगियों के तौर पर श्रवण सम्पत्ति की गयी विशिष्ट सेवाओं श्रवण प्रबन्ध व्यवस्था के लिए कमीशन के रूप में श्रवण किसी वैक उद्यम के मामले को छोड़कर, उद्यम के प्रधान कार्यालय को श्रवण उसके अन्य कार्यालयों में में किसी कार्यालय को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) प्रभास्ति की गयी हों।

४. जहाँ किसी संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न भागों में अनुभाजित किए जाने के अधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए माने जाने वाले लाभों को तथ करने की प्रथा रही हो, वहाँ पैराग्राफ २ की कोई भी व्याख्या उस संविदाकारी राज्य को ऐसी प्रथागत अनुभाजन पद्धति में कर लगते वाले लाभों का निर्धारण करने से प्रतिवाधित नहीं करेगी, लेकिन अपनाई गयी अनुभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुसार होगा।

५. कोई लाभ केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के निए मान या पर्यावरण-वस्तु खीरे गयी है।

६. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाना रहेगा जब तक उसके विवरण कोई उचित तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

७. जहाँ लाभों में श्राय की वे मर्दे शामिल हैं जिनका उस कारण के अन्य अनुच्छेदों में अन्य गति देने से विवेचन किया गया है, वहाँ उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद ८

निवाहन तथा विमान परिवहन

१. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जनयानों अवधा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जायेगा।

२. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ १ के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अवधा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्राप्तियांत में जलयान अथवा वायुयान के परिचालन से संबंधित निवासी पर के ब्याज को ऐसे जलयान अथवा वायुयान के परिचालन से प्राप्त लाभ माना जाएगा तथा अनुच्छेद 11 के उपबन्ध ऐसे ब्याज के मामत्रे में लागू नहीं होंगे।

4. “जलयान अथवा वायुयान परिचालन” पद से तात्पर्य होगा—जलयान अथवा वायुयान के मालिकों अथवा पट्टेवारों अथवा अवक्षेत्रों द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल के परिवहन कारोबार, जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, जलयान अथवा वायुयान का आकस्मिक पट्टा तथा ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 9

सम्बद्ध उद्यम

1. जहा—

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबन्ध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबन्ध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूँजी में ब्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं, और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्त रखी अथवा लगाई जाती है, जो उन शर्तों से भिन्न है जो कि स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों में नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जाएगा।

2. जहा कोई संविदाकारी राज्य अपने लाभों को उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में शामिल करता है और उन लाभों पर तदनुसार कर लगाता है, जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार के शामिल किए गए लाभ वे लाभ हैं जो प्रयोग्यलिखित राज्य के उद्यम को प्राप्त हुए होते, यदि दो उद्यमों के बीच रखी गई शर्तें वही थीं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी गई होती, तो वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उस राज्य में लगाए गए कर की राशि का उचित समायोजन करेगा। ऐसे समायोजन का निर्धारण करते समय इस करार के अन्य उपबन्धों की ओर भी सम्यक् ध्यान देना होगा और संविदाकारी राज्यों के मध्यम प्राधि-

कारियों को, यदि आवश्यक हुआ, एक दूसरे से परामर्श करना होगा।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की किसी निवासी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए गए लाभांशों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकता है।

2 तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस मंधिदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिस राज्य की लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है और यह कर उस राज्य के कानूनों के अनुसार लगेगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा।

(क) लाभांशों की सकल रकम का 10 प्रतिशत, यदि हितभागी स्वामी कोई ऐसी कम्पनी है जो लाभांश अदा करने वाली कम्पनी के शेयरों की कम से कम पच्चीस प्रतिशत की स्वामी हो;

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभांश की सकल रकम का 15 प्रतिशत।

यह पैराग्राफ ऐसे लाभों के मामले में कम्पनी के कराधान को त्रावित नहीं करेगा जिसमें से लाभांश अदा किए जाते हैं।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “लाभांश” पद का अर्थ है—शेयरों से अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय, जो अदृष्ट दावे नहीं हैं, लाभों में सम्मिलित हों, तथा अन्य निर्गमित अधिकारों से प्राप्त आय जिस पर उसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी कि वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य की निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी कि लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से उसमें स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं सम्पन्न करता हो और वह सम्पत्ति जिसके संबंध में लाभांश अदा किए जाते हैं, इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हों। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबन्ध में यथास्थिति लागू होंगे।

5. जहाँ कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है और वह दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ वह दूसरा राज्य उस कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, सिवाय इसके कि जहाँ तक कि उसे दूसरे राज्य के किसी निवासी को इस प्रकार के लाभांश अदा किए जाते हैं अथवा जहाँ तक कि वह सम्पत्ति जिसके संबंध में लाभांश अदा किए जाते हैं, उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी मंस्थापन में अथवा किसी निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है, और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर लगाया जा सकते वाला कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद 11

ब्याज

1. एक मंविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को प्रदत्त ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, ऐसे ब्याज पर, उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वह उद्भूत होता है उस राज्य की विधियों के अनुसार कर लगाया जाएगा परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर उक्त ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपनिषदों के बायजूदः

(क) एक मंविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी यदि यह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा लाभप्रद रूप से धारित हों;

(1) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, कोई राजनैतिक उप प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा

(2) दूसरे संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः धारित केन्द्रीय बैंक अथवा कोई ऐंजेंसी अथवा सहायता केन्द्र (जिसमें वित्तीय संस्था भी शामिल है।)

(ख) किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में उस राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा तक कर से

छूट दी जाएगी, यदि वह ब्याज उप पैरा (क) में उल्लिखित व्यक्ति से मिल उस अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो और लाभप्रद रूप से धारित किया गया हो, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, वश्ते कि प्रथमोक्त मंविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा इस संबंध में अहं दावे के लिए लेन-देन के मामले को अनुमोदित किया गया हो।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “ब्याज” शब्द का अभिप्राय मध्ये प्रकार के अहं दावों से प्राप्त आय में है (जिसमें विक्री की आस्थगित अदायगिया पर ब्याज भी शामिल है), चाहे वह बन्धक के रूप में आरक्षित रखी गयी हो अथवा नहीं रखी गयी हो और चाहे उसके बारे में कर्जदार के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं प्राप्त हो और विषेषतः सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय और बंध पक्षों अथवा अहं फक्तों से प्राप्त होने वाली आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध-पक्षों अथवा अ-पक्षों के साथ जुड़े लाभ तथा पुरस्कारों से प्राप्त आय भी शामिल है। देर से की गयी अदायगी के लिए नगाएँ गए अर्थवद्धण को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस विधि में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी मंस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाना हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत मेवाएं प्रदान करना हो और जिस अहं-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान में प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसा भी मामला हो, लागू होगे।

6. किसी मंविदाकारी राज्य में उस स्थिति में ब्याज उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज शदा करने वाले स्वयं वह मंविदाकारी राज्य, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उक्त राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु जहाँ ब्याज शदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा नहीं है, मंविदाकारी राज्य में कोई स्थायी मंस्थापन है अथवा ऐसा कोई निश्चित स्थान है, जिसके मध्य में वह करण लिया गया था और जिस पर ब्याज की अदायगी की गयी हो और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी मंस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा बहन किया जाता है तब वह ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिसमें उक्त स्थायी मंस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7 जहा व्याज श्रद्धा करने वाले तथा लाभ-भोगी रवामी के बीच अथवा उन दोनों तथा किसी ग्रन्थ व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का कोई सम्बंध होने के कारण, व्याज की रकम उस क्रूण-दावे का ध्यान में रखने हुए, जिसके लिए इसकी अदायगी की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के सबध नहीं होने की स्थिति में, व्याज श्रद्धा रखने वाले तथा हितभागी स्वामी के बीच गहमति हुई होती, तो ऐसे मामले में इस अनुच्छेद के उपबध केवल अतिम वर्णित रकम पर लागू होगे। इस प्रकार के मामले में अदायगी के अतिरिक्त भाग पर इस करार के अन्य उपबन्धों का सयक ध्यान रखते हुए प्रत्येक सविदाकारी राज्य की विधियों के अनुसार कर लगेगा।

अनुच्छेद 12

रायलिट्या

1 एक सविदाकारी राज्य में उद्भूत तथा दूसरे सविदा कारी राज्य के किसी निवासी को प्रदत्त रायलिट्यों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2 तथापि, ऐसी रायलिट्यों पर उस सविदाकारी राज्य में जिसमें वे उद्भूत होती हैं और उसी राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जाएगा परन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायलिट्यों का हितभागी स्वामी हो तो उस प्रकार लगाया गया कर रायलिट्यों की मकल रकम के 15 प्रतिशत में अधिक नहीं होगा।

3 इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “रायलिट्या” शब्द का नात्पर्य—साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृति किसी कापीराइट जिम्मे रेडियो अथवा दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए प्रयुक्त चलचित्र-फिल्म, अथवा फिल्में या टेपें भी शामिल हैं, कोई पेटेट, ट्रैडमार्क, डिजाइन अथवा माडल, ज्लान गूण फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव ने सबधित गूचना के लिए प्रतिपत्ति के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की रकम में है।

4 वैग्राम 1 तथा 2 के उपबध उस स्थिति में नागू नहीं होगे, यदि रायलिट्यों का हितभागी स्वामी एक सविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे सविदाकारी राज्य में, जहा रायलिट्यों उद्भूत होती हो, वहा स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, अथवा उस दूसरे राज्य में बढ़ा स्पृति किसी निश्चित स्थान में स्वतंत्र व्यक्तिगत मेवाण गिराविन करता है, तथा ऐसे अधिकार अथवा मम्पति जिसके सबध में रायलिट्या श्रद्धा की जाती है, ऐसे स्थायी मस्थापन अथवा निश्चित स्थान में प्रभावी रूप से गवधित है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 14 के जैसा भी मामला हो, उपबंध लागू होगे।

5 रायलिट्या एक सविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जब अदाकर्ता स्वयं वह गज्ज, कोई गजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राविकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु जहा रायलिट्या अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह एक सविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा नहीं, किसी सविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान है जिसके संबंध में रायलिट्यों की अदायगी करने की जिम्मेदारी उपगत थी, तथा ऐसी रायलिट्या ऐसे स्थायी मस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वाग वहन की जाती है तब ऐसी रायलिट्या उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें स्थायी मस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6 जहा अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का सबध होने के कारण रायलिट्यों की रकम, प्रयोग, अधिकार अथवा मूचना को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए रायलिट्यों की अदायगी की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिस पर ऐसे संबंधों के नहीं होने पर अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी द्वारा सहमति हो गयी होती, तो वहा इस अनुच्छेद के उपबध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होगे। ऐसे मामले में अधिक श्रद्धा की गयी रकम इस करार के अन्य उपबधों का यथोक्ति ध्यान रखते हुए प्रत्येक सविदाकारी राज्य की विधियों के अनुमान करार्थी होगी।

अनुच्छेद 13

पूर्णीगत अभिलाभ

1 एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित अबल मम्पति के अन्तरण में प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2 चल सपत्नि के अन्तरण ने प्राप्त हुए अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के किसी स्थायी संस्थापन की व्यापारिक मम्पति के अग-रूप में दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित है अथवा जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे सविदाकारी राज्य में उपलब्ध किसी निश्चित स्थान में सबधित चल मम्पति हो, जिसमें ऐसे स्थायी मस्थापन (अकेले अथवा मम्पूर्ण उद्यम वे साथ) अथवा ऐसे निश्चित रथान के अन्तरण से होने वाले ऐसे अभिलाभ भी शामिल हैं, उन पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सके गा।

3 अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जनयात्रों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के सञ्चालन में सबधित चल सम्पत्ति रे अन्तरण में प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस सविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका कि अन्तरणकार्ता निवासी है।

4. पैराग्राफ 1, 2 और 3 में उल्लिखित मन्त्रालय ने भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभा पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरकर्ता निवासी है।

अनुच्छेद 14

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी हारा व्यावरायिक सेवाओं अथवा उसी स्वरूप के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों के निष्पादन में प्राप्त आय, निम्ननिमित्त परिस्थितियों को छोड़कर, जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कराधेय होगी :

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान निर्मित रूप से उपबन्ध है तो उस मामले में उप दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उम निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई भारी जा भारी है, अथवा,

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधिया किसी 12 माह की अवधि में 91 दिन अरमा कुल मिलाकर उसमें अधिक हो तो उस मामले में, उस आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो स दूसरे राज्य में निरपादित उनके कार्यकलापों से प्राप्त होती हो।

2. “व्यावसायिक सेवाएं” पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, माहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा खिलिकों, शल्यचिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दल्तन्त्रिकित्सकों तथा लेखापालों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 15

पराश्रित व्यक्तिगत सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 17, 18, 19, 20 और 21 के उपबन्धों के अधीन रहने हुए एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी हारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेनन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा जब तक कि उस नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में सम्पन्न नहीं किया गया हो। यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो बहुत गे प्राप्त होता है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी हारा दूसरे संविदाकारी राज्य

में सम्पन्न किए गए किसी नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोलिंगित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता दूसरे राज्य में किसी माह बारह माह की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन से अनधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए मौजूद रहा हो, और

(ख) पारिश्रमिक किसी ऐसे नियोजन द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया हो जो उस दूसरे राज्य का निवासी नहीं है, और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा किसी निश्चित स्थान से बहन नहीं किया गया हो, जो नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उच्चम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय प्रातायात में किसी जलयान अथवा किसी वायुयान पर सवार ढोकर उसके परिचालन में सम्पन्न किए गए किसी नियोजन के मंबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल उस राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 16

निवेशकों की फीस

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी के निदेशक-मण्डल के एक सदस्य की हैमियत (चाहे किसी भी नाम से इसे बुलाया जाए) से जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस तथा उससे मिलती-जुलती अदायगियों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 17

मनोरंजनकर्ता तथा खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता के रूप में, जैसे कि एक थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा एक संगीतकार अथवा एक खिलाड़ी के रूप में अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों से, जिन्हें वह दूसरे संविदाकारी राज्य में सम्पन्न करता है, प्राप्त आय पर कर उस दूसरे राज्य में लग सकेगा।

2. जहाँ किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा इस प्रकार की अपनी हैमियत में सम्पन्न किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापों के सम्बन्ध में उद्भूत आय स्वयं उस मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती है प्रपितु किसी ग्रन्थ अधिकार को प्राप्त होती है, वहाँ अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबन्धों के होते हुए भी उस आय पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिसमें उक्त मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे कार्यकलाप मम्पन किए गए हों।

3 पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी हैसियत में सम्पन्न किए गए अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों से अर्जित आय प्रथमोलिखित राज्य में कर योग्य होगी, यदि :

(क) दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्यकलाप प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से जिसमें उसका कोई राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित हो, अथवा

(ख) दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्यकलाप दोनों संविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच स्वीकृत सांस्कृतिक आदान-प्रदान के किसी कार्यक्रम विशेष के अनुमरण में है।

4. पैराग्राफ 2 और अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी उसी हैसियत में एक संविदाकारी राज्य में सम्पन्न किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापों के सम्बन्ध में उद्भूत आय, स्वयं उम मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती है परन्तु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस भागमें में वह आय केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी, यदि :

(क) वह दूसरा व्यक्ति उम दूसरे राज्य की, जिसमें उसका कोई राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित किया गया हो, अथवा

(ख) दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी होने के कारण किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कार्यकलापों को निष्पन्न किया जाता है, जो दोनों संविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच स्वीकृत सांस्कृतिक आदान-प्रदान के किसी कार्यक्रम विशेष के अनुसरण में हैं तथा जिस अन्य व्यक्ति को वहां से आय प्राप्त होती है, वह दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है।

अनुच्छेद 18

सरकारी सेवा के सम्बन्ध में पारिश्रमिक तथा पेशन

1. एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उम राज्य अथवा उसके उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए सम्पन्न की गई सेवाओं के निमित्त प्रदत्त किसी पेशन से भिन्न, पारिश्रमिक पर कर केवल उम राज्य में ही लग सकेगा। लेकिन ऐसे पारिश्रमिक पर कर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल नव लग सकेगा यदि

मेवाएं उस दूसरे राज्य में सम्पन्न की जाती है तथा वह व्यष्टि उस राज्य का एक निवासी है जो :

(क) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है ; अथवा

(ख) मात्र सेवाएं देने के प्रयोजनार्थ उस राज्य का एक निवासी नहीं बना था।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा बूजित किए गए कोष में से किसी व्यक्ति को उसके द्वारा उम राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के निमित्त सम्पन्न की गई सेवाओं के लिए प्रदत्त किसी पेशन पर कर केवल उम राज्य में ही लग सकेगा। किन्तु ऐसी पेशन दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उस स्थिति में ही कराधेय होगी यदि व्यष्टि उस राज्य का एक निवासी तथा एक राष्ट्रिक है।

3. अनुच्छेद 15, 16 और 17 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न किए गए कारोबार के सिलमिले में की गई सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुए पारिश्रमिक और पेशन पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 19

गैर-सरकारी पेशन तथा वार्षिकी

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर स्थित स्थोतों से प्राप्त किसी पेशन पर, जो अनुच्छेद 18 में उल्लिखित पेशन से भिन्न हो, अथवा किसी वार्षिकी पर कर केवल प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में ही लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य (अथवा उसके प्राधिकृत अधिकरण) की सरकार द्वारा अनुमोदित किसी पेशन निधि में से दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के विगत नियोजन को ध्यान में रखते हुए अथवा की गई पेशन पर प्रथमोलिखित राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. “पेशन” शब्द में विगत सेवाओं के प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान हुए जर्मों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में की जाने वाली कोई आवधिक अदायगी अभिप्रेत है।

4. “वार्षिकी” शब्द से जीवन-काल में अथवा विनिर्दिष्ट अथवा निष्चय समयावधि के दौरान धन अथवा धन के बराबर पर्याप्त सथा पूर्ण प्रतिफल के बदले में अदायगी करने के लिए किसी इकारार के अन्तर्गत निश्चित समय में आवधिक आधार पर अदायगी योग्य कोई निश्चित राशि अभिप्रेत है।

अनुच्छेद 20

विद्यार्थी और प्रशिक्षण

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दीर्घ करने के तुरन्त पहले दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो भाव अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है, निम्नलिखित पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी :

- (क) उस दूसरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस की गई अदायगियाँ; और
- (ख) उस दूसरे राज्य के किन्हीं बारह माह की अवधि के दौरान नियोजन में प्राप्त पारिश्रमिक ज्ञां, 20,000 रु. अथवा 2,000,000 रु. से अधिक न हो, जैसा भी भामला हो, बशर्ते कि ऐसा नियोजन प्रत्यक्षतः उसके अध्ययन से संबंधित हो अथवा भरण-पोषण के प्रयोजनार्थ किया जाता हो।

2. इस अनुच्छेद का लाभ केवल ऐसी समय-अवधि तक के लिए प्राप्त होगा जो उक्त शिक्षा अथवा शुरू किए गए प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया प्रपेक्षित हो परन्तु इस अनुच्छेद का लाभ किसी व्यष्टि को किसी भी हालत में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसे पहली बार पहुंचने की तारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए प्राप्त नहीं होगा।

अनुच्छेद 21

प्राध्यापक, अध्यापक और शोध-छात्र

1. किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य अनुमोदित संस्था में अध्यापन अथवा शोधकार्य के प्रयोजनार्थ अथवा दोनों कार्यों के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में जाने के तुरन्त पूर्व दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था, ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके पहुंचने की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद उस शोध-कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध-कार्य मुख्यतः किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो।

3. इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 20 के प्रयोजनार्थ किसी व्यष्टि को एक संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा, यदि वह उस आय वर्ष में उस संविदाकारी राज्य का निवासी हो जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा उस आय वर्ष के तत्काल पूर्व वर्ष में।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ “मन्यता प्राप्त संस्था” का अर्थ एक ऐसी संस्था से है जिसे इस संबंध में संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी गई है।

अनुच्छेद 22

अन्य आय

1. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मद्दें, जहां कहीं वे उद्भूत होती हों, और जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में करार्धेय होगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथापरिस्थित अचल संपत्ति से प्राप्त आय से मिल आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उग दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा संपत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निष्पित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसा भी स्थिति हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मद्दों पर भी जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती है, उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद 23

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय कर कराधान के मामलों में लागू रहेंगे लेकिन ऐसे मामलों को छोड़कर जहां पर इस करार में उनके विपरीत कोई प्रावधान किया जाता है।

2. इंडोनेशिया के कानूनों के अंतर्गत तथा इस करार के उपबंधों के अध्यधीन संदेश इंडोनेशियाई कर, जिसे भारत के किसी निवासी द्वारा इंडोनेशिया में उद्भूत हुए लाभ अथवा आय के संबंध में प्रत्यक्ष रूप में अथवा कटीती करके अदा किया गया हो और जिस कर पर भारत तथा इंडोनेशिया दोनों देशों में कर लगाया जा सकता है, ऐसे लाभों अथवा आय पर संदेश भारतीय कर में से कटीती के रूप में अनुमत्य होगा बशर्ते कि ऐसे लाभ की रकम उस भारतीय कर (इस प्रकार की कटीती की अनुमति दिए जाने से पूर्व व्यापारसंगति) से अधिक नहीं होनी चाहिए जो इंडोनेशिया में उद्भूत हुए।

लाभों अथवा आय के लिए समुचित है। इसके अतिरिक्त, जहां ऐसा निवासी कोई कंपनी है, जिसके कारण भारत में अतिकर संदेय है, तो ऐसे मामले में उपर्युक्त कटौती की अनुमति कंपनी द्वारा भारत में संदेय आयकर के प्रति तथा उसके द्वारा भारत में संदेय अतिकर की पोष रकम के प्रति, यदि कोई हो, प्रथम बार मिलेगी।

3. “संदेय इंडोनेशियाई कर” में इंडोनेशियाई कर की वह रकम भी शामिल की गई मानी जाएगी जो उस स्थिति में अदा कर दी गई होती यदि उस पर 1983 के कानून संख्या 7 (अनलांग-अनलांग पाजाक पेंदासिलन 1984) के अनुच्छेद 33 के तहत किए गए प्रोत्साहन संबंधी ऐसे विशेष उपायों के अनुमार छूट नहीं दी गई होती अथवा उस पर कटौती नहीं की गई होती जिन उपायों का निर्माण इंडोनेशिया के आर्थिक विकास का संबद्धन किए जाने के उद्देश्य से किया गया है और जो इस करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख को प्रभावी हैं अथवा जिन्हें इंडोनेशिया में आर्थिक विकास का संबद्धन किए जाने के लिए विद्यमान उपबंधों में भविष्य में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्थन करके पुरस्थापित किया जा सकता है और प्रोत्साहन संबंधी अन्य ऐसे उपाय जिन पर संविदाकारी राज्यों के बीच समय-समय पर सहमति प्राप्त हो सकती है।

4. इंडोनेशिया के किसी निवासी द्वारा भारत में उद्भूत हुए लाभों अथवा आय के संबंध में, जिस पर भारत तथा इंडोनेशिया, दोनों राज्यों में कर लगाया गया हो, प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती करके भारत के कानूनों के अंतर्गत तथा इस करार के उपबंधों के अनुमार संदेय भारतीय कर की रकम पर ऐसे लाभों अथवा आय पर संदेय इंडोनेशियाई कर के प्रति कटौती की अनुमति प्राप्त होगी बशर्ते कि ऐसी कटौती की रकम उस इंडोनेशियाई कर (इस प्रकार की कटौती की अनुमति दिए जाने से पूर्व यथा-संगणित) से अधिक नहीं हो जो भारत में उद्भूत हुए लाभों अथवा आय के अनुरूप हों।

5. “संदेय भारतीय कर” में भारतीय कर की वह राशि भी शामिल की गई मानी जाएगी जो उस स्थिति में अदा कर दी गई होती यदि उस पर भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के तहत किए गए प्रोत्साहन संबंधी ऐसे विशेष उपायों के अनुसार छूट नहीं दी गई होती अथवा उस पर कटौती नहीं की गई होती जिन उपायों का निर्माण भारत में आर्थिक विकास का संबद्धन किए जाने के उद्देश्य से किया गया है और जो इस करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख को प्रभावी है अथवा जिन्हें भारत में आर्थिक विकास का संबद्धन किए जाने के लिए विद्यमान उपबंधों में भविष्य में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्थन करके पुरस्थापित किया जा सकता है और प्रोत्साहन संबंधी ऐसे उपाय जिन पर संविदाकारी राज्यों के बीच समय-समय पर सहमति प्राप्त हो सकती है।

अनुच्छेद 24

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई प्रपेक्षा लागू नहीं होगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर एक समान परिस्थितियों में लागू होनी है अथवा हां सकती है।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी स्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं होगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर एक समान परिस्थितियों में समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम प्रत्यक्ष हो।

3. इस अनुच्छेद में, निम्न इसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के उन व्यक्तियों को, जो उस राज्य के निवासी नहीं है, कराधान के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार की व्यक्तिगत छूट, राहत, कटौतियां तथा घटी-तिपा मंजूर करने के लिए, जो कि कानून द्वारा केवल ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध हैं जो वहां के निवासी हैं, उपकृत करना है।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूँजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियन्त्रण में है, प्रयोजन संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा नवनीती कोई भी अपेक्षा लागू नहीं होगी जो उस कराधान से तथा किन्हीं भी संबंधित अपेक्षाओं से, भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोलिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर एक समान परिस्थितियों के अधीन लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है।

5. इस अनुच्छेद में “कराधान” शब्द का अर्थ उन करों से है जो इस करार के विषय है।

अनुच्छेद 25

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. अहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार का कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत उपबंधित उपायों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य के सधाम आधिकारी के पास अन्त मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह निवासी है। इस मामले को उस कार्यवाही के मोटिम के प्राप्त होने की तारीख से, तीन वर्ष के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिए,

गियरे का राण लगाया गया कर इस करार के अनुकूल नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपसि उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी समुचित समाधान पर पहुँचने में अग्रमर्य हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से, जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर महमति से उस मामले का समाधान करने का प्रयास करेगा। किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्य के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी गमय सीमा क्यों न हो।

3. यदि इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हे पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर मिलते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं थी गई है।

4. पूर्ववर्ती पैराश्राफों के अभिप्राय में कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ सांविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पक्ष-व्यवहार कर सकते हैं। जहां समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मार्गिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त समझा जाता हो वहां इस करार का विचार-विमर्श किसी आयोग के माध्यम से किया जा सकता है। जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

अनुच्छेद 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (जिसमें दस्तावेज भी शामिल हैं) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आन्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, जो इस करार के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान-व्यवस्था करार के प्रतिकूल नहीं हो ताकि विशेष रूप से ऐसे करों की धोखाधड़ी अथवा अपवंचन रोका जा सके।

किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार की उस राज्य के आन्तरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की, गई सूचना मानी जाती है। लेकिन यदि सूचना भेजने वाले राज्य में उक्त सूचना को मूलतः गुप्त समझा जाता है तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण करने अथवा उनकी बगूनी करते, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा

उनमें संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से सम्बद्ध हों, जो इस करार के विषय है। ऐसे अक्तिअथवा प्राधिकारी उक्त सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु व उक्त सूचना को सर्वजनिक न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक विधियों में प्रकट कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शब्दों, पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा जिनमें, जहां कही उपयुक्त हो, कर एवं परिहार के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नेपी आधार पर अथवा मामलों-विशेष के संदर्भ में अनुरोध करने पर अथवा धोनों स्थितियों में किया जा सकेगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी सम्बन्ध-समय पर, ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची के बारे में सहमत होगी, जिसे एक नेपी आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

3. किसी भी स्थिति में, पैराश्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना जो उग अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना जिनमें कोई व्यापारिक, व्यावहारिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भंड अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो अथवा ऐसी सूचना, जिसको प्रकट करना नार्यजनिक नीति के प्रतिकूल है।

अनुच्छेद 27

राजनयिक और कांसुली कार्यकलाप

इस करार की किसी भी बात से राजनयिक अथवा कांसुली अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत प्राप्त विस्तीर्ण विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 28

प्रबन्धन

दोनों संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य, इस करार को लागू करने के लिए अपनी विधि के अंतर्गत अपेक्षित कार्यविधियों के पुरा किए जाने के बारे में दूसरे राज्य को

अधिसूचित करेगा। यह करार इन अधिसूचनाओं में से बाद में जारी की गई अधिसूचना की तारीख से लागू होगा और इसका निम्नलिखित प्रभाव होगा :

- (क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में बाद की अधिसूचनाएं दी गई हों, उस कैलेंडर वर्ष के अगले किसी भी परवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी भी पिछले वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में;
- (ख) इंडोनेशिया में, जिस कैलेंडर वर्ष में बाद की अधिसूचनाएं दी गई हों, उस कैलेंडर वर्ष के अगले किसी भी परवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी भी आय-वर्ष में उद्भूत हुई आय के संबंध में।

अनुच्छेद 29

समाप्ति

यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा जेकिन दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात शुरू होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष में जून के तीसवें दिन को अथवा उसमें पहले, राजनयिक माध्यमों से, दूसरे संविदाकारी राज्य को समाप्ति का लिंगित रूप में नोटिस दे सकेगा और ऐसी स्थिति में यह करार निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा :

- (क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, उस कैलेंडर वर्ष के अगले परवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी भी पिछले वर्ष में उद्भूत हुई आय के संबंध में;
- (ख) इंडोनेशिया में, जिस कैलेंडर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, उस कैलेंडर वर्ष के अगले परवर्ती वर्ष के जनवरी भास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात आरंभ होने वाले किसी भी आय-वर्ष में उद्भूत हुई आय के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताधरियों ने वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

जकारता में वर्ष एक हजार ना सौ सत्तामी के माह अगस्त के मातवें दिन को, हिम्दी, बहाशा इंडोनेशिया तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्प्रब्र किया गया, जिनके सभी पाठ भास्तवतः प्रामाणिक हैं। अर्थ-निष्पत्ति की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा ।

ह.

विनोद खन्ना
भारत गणराज्य की
राजकार की ओर से

ह.

रूसली तूर
इण्डोनेशिया गणराज्य की
सरकार की ओर से

प्रांतोकोल

आय पर करा के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवर्चन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और इण्डोनेशिया गणराज्य की सरकार उक्त करार पर हस्ताक्षर करते समय निम्नलिखित उपबन्धों पर सहमत हो गई हैं, जो इस करार के अभिन्न अंग होंगे :

1. अनुच्छेद 7 के प्रयोजनार्थ, जहां कोई कम्पनी दोनों राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य की निवासी है और उसका दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन स्थित है, तो उस स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों पर उस दूसरे राज्य में उसके कानून के अनुसार अतिरिक्त कर लगाया जा सकेगा लेकिन यह अतिरिक्त कर ऐसे लाभों में में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उन पर लगाए जाने वाले आयकर की तथा आय पर अन्य करों की कटौती किए जाने के पश्चात् उक्त लाभों की बकाया राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

2. इण्डोनेशिया की सरकार द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जो भारत का निवासी है, तेल और गैस थेट्र अथवा अन्य ऊपर उद्योग के लिए तथा विए गए अथवा निष्प्रब्र किए गए उत्पादन में भागीदारी के किसी भी करार तथा कार्य के लिए करार (अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य करार) में निहित उपबन्धों पर, उसकी लिखित, उसकी सम्बन्धित राजकीय तेल तथा गैस कम्पनी अथवा उसकी किसी अन्य सत्ता पर जनवरी, 1984 के प्रथम दिन से पूर्व पैराग्राफ 1 के उपबन्धों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

3. अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 के उपबन्ध किसी तीसरे देश में किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की शाखा को उद्भूत होने वाले ब्याज पर भी लागू होंगे ।

4. अनुच्छेद 24 के उपबन्धों के होते हुए भी, इस करार के उपबन्धों का अर्थ अब अथवा बाद में दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के अपवर्जन, छूट, कटौती, लाभ अथवा अन्य छूट पर निम्नलिखित द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना नहीं होगा:—

(क) दोनों राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्यों के कानूनों द्वारा उस संविदाकारी राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर के निर्धारण के मामले में, अथवा

(ख) दोनों संविदाकारी राज्यों के बीच ग्राहिक अथवा तकनीकी सहयोग के लिए कराधान के सम्बन्ध में कोई गई किसी अन्य विशेष व्यवस्था के द्वारा ।

जिसके गाथ्य में इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधो-हस्ताक्षरियों ने इस प्रतीकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

जकार्ता में वर्ष एक हजार नौ सौ सत्तामी के माह अगस्त के सातवें दिन को हिन्दी, बहाशा इण्डोनेशिया तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निलम्ब किया गया, जिसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक हैं। अर्थ-निरूपण की विश्वता के मामले में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

ह./-

ह./-

विनोद खस्ता
भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

रुसली नूर
इण्डोनेशिया गणराज्य की
सरकार की ओर से

[सं. 7774 फा. म. 11/30/69-एफ टी डी]

ह./-

पी० के० अपानू, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

New Delhi, the 4th February, 1988

NOTIFICATION

INCOME-TAX

G.S.R. 77 (E) :—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Indonesia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has entered into force on the 19th December, 1987 on the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required by their laws, as specified by Article 28 of the said agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Indonesia,

DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

HAVE AGREED as follows :

ARTICLE 1

Personal Scope

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2.

Taxes Covered

1. The taxes to which this Agreement shall apply are :

(a) in India :

- (i) the income tax including any surcharge thereon imposed under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) ;
- (ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964) ;

(hereinafter referred to as "Indian Tax").

(b) in Indonesia :

the income tax imposed under the Undang-undang Pajak Penghasilan 1981 (Law No. 7 of 1981) and to the extent provided in such income tax law, the company tax imposed under the Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (State Gazette No. 319 of 1925 as lastly amended by Law No. 8 of 1970) and the tax imposed under the Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970 (Law No. 10 of 1970) ;

(hereinafter referred to as "Indonesian Tax").

2. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

ARTICLE 3

General Definitions

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and air space above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereignty,

sovereign rights, other rights and jurisdiction according to the Indian Law and in accordance with International Law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982;

- (b) the term "Indonesia" comprises the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and the adjacent areas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law, particularly the provisions of the United Nations Conventions on the Law of the Sea, 1982;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Indonesia as the context requires;
- (d) the term "tax" means Indian tax or Indonesian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
- (e) the term "person" includes an individual a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (i) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and in the case of Indonesia, the Minister of Finance or his authorized representative;
- (j) the term "national" means any individual, possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in the Contracting State.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

ARTICLE 4

Resident

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the contracting States shall settle the question by mutual agreement keeping in view its place of incorporation, place of effective management and other relevant factors.

ARTICLE 5

Permanent Establishment

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, but only where

such site, project or activity continues for a period of more than 183 days.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

4. Where a person (other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 7 apply) is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if :

- (a) that person has, and habitually exercises in the first-mentioned State, an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise; or
- (b) that person maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it furnishes services, including consultancy services in that other Contracting State through employees or other personnel—other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 7 apply,—provided that activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than 91 days in any twelve month period.

6. An insurance enterprise of a Contracting State shall, except with regard to reinsurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in that other State or insures risks situated therein through an employee or through a representative who is not an agent of an independent status within the meaning of paragraph 7.

7. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other state through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6

Income From Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property, including income from agriculture or forestry, situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, ususfruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7

Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment, for amounts charged (otherwise than in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. In so far as it has been customary in a contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary, the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other articles of this

Agreement, then the provisions of those articles shall not be affected by the provisions of this article

ARTICLE 8

Shipping and Air Transport

1 Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State

2 The provisions of paragraph 1 of this article shall also apply to profits from participation in a pool, a joint business or an international operating agency

3 For the purposes of this article, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft and the provisions of article 11 shall not apply in relation to such interest.

4 The term "operation of ships or aircraft" shall mean business of transportation of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of ships or aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of ships or aircraft and any other activity directly connected with such transportation

ARTICLE 9

Associated Enterprises

1 Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2 Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State—and taxes accordingly—profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which

would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of the agreement and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.

ARTICLE 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed :

- (a) 10 per cent of the gross amount of dividends if the beneficial owner is a company which owns at least twenty five per cent of the shares of the company paying the dividends ;
- (b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment of fixed base. In such case, the provisions of article 7, or article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other

State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 :

- (a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :
 - (i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or
 - (ii) the Central Bank or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by the other Contracting State or political sub-division or local authority thereof.
- (b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State to the extent approved by the Government of that State if it is derived and beneficially owned by any person (other than a person referred to in sub-paragraph (a)) who is a resident of the other Contracting State provided that the transaction giving rise to the debt-claim has been approved in this regard by the Government of the first-mentioned Contracting State.

4. The term "interest" as used in this article means income from debt-claim of every kind (including interest on deferred payment sales), whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed

base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provision of article 7 of article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 12

Royalties

1. Royalties in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, my copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or

fixed base. In such case, the provisions of article 7 or article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 13

Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 14.**Independent Personal Services**

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :—

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State;

or

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 91 days in any twelve month period; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 15**Dependent Personal Services**

1. Subject to the provisions of articles 16, 17, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of

a Contracting State shall be taxable only in that State.

ARTICLE 16**Directors' Fees**

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors (by whatever name called) of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 17**Entertainers and Athletes**

1. Notwithstanding the provisions of articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste or a musician or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. While income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of articles 7, 11 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable in the first-mentioned Contracting State if :

(a) the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political sub-divisions or local authorities, or

(b) the activities in the other Contracting State are in pursuance of a special programme for cultural exchange agreed upon between the Governments of the two Contracting States.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and articles 7, 14 and 15, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State if :

(a) that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political sub-divisions or local authorities, or

(b) the activities are exercised by an individual, being a resident of the other Contracting State, in pursuance of a special programme

for cultural exchange agreed upon between the Governments of the two Contracting States and that other person to whom income therefrom accrues is a resident of the other Contracting State.

ARTICLE 18

Remuneration and Pensions in Respect of Government Service

1. Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State. However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who :

- (a) is a national of that State; or
- (b) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State. However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof.

ARTICLE 19

Non-Government Pensions and Annuities

1. Any pension, other than a pension referred to in article 18, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid out of a pension fund approved by the Government of a Contracting State (or its authorised Agency) to a resident of the other Contracting State in consideration of past employment may be taxed in the first-mentioned State.

3. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

4. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

ARTICLE 20

Students and Apprentices.

1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on :

- (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and
- (b) remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding Rs. 20,000 or Rs. 2,000,000 during any twelve month period, as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefits of this article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this article for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

ARTICLE 21

Professors, Teachers and Research Scholars

1. A professor or teacher who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.

2. This article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this article and article 20, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the year of income, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding year of income.

4. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

ARTICLE 22

Other Income

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt

with in the foregoing articles of this Agreement, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of article 7 or article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

ARTICLE 23

Elimination of Double Taxation

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. The amount of Indonesian tax payable, under the laws of Indonesia and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of profits or income arising in Indonesia, which have been subjected to tax both in India and in Indonesia, shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed the Indian tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the profits or income arising in Indonesia. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income tax payable by the company in India and as to the balance, if any, against surtax payable by it in India.

3. The term "Indonesian tax payable" shall be deemed to include the amount of Indonesian tax which would have been paid if the Indonesian tax had not been exempted or reduced in accordance with the special incentive measures under Article 33 of Law No. 7 of 1983 (Undang-undang Paiak Penghasilan 1984) which are designed to promote economic development in Indonesia, effective on the date of signature of this Agreement, or which may be introduced in the future in modification of, or in addition to, the existing provisions for promoting

economic development in Indonesia, and such other incentive measures which may be agreed upon from time to time by the Contracting States.

4. The amount of Indian tax payable under the laws of India and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of Indonesia, in respect of profits or income arising in India, which has been subjected to tax both in India and in Indonesia, shall be allowed as a credit against Indonesian tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed the Indonesian tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the profits or income arising in India.

5. The term "Indian tax payable" shall be deemed to include the amount of Indian tax which would have been paid if the Indian tax had not been exempted or reduced in accordance with the special incentive measures under the provisions of the Indian Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), which are designed to promote economic development in India, effective on the date of signature of this Agreement, or which may be introduced in the future in modification of, or in addition to, the existing provisions for promoting economic development in India, and such other incentive measures which may be agreed upon from time to time by the Contracting States.

ARTICLE 24

Non-Discrimination

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances.

3. Nothing contained in this article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of

the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.

5. In this article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

ARTICLE 25

Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 26

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of the State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 27**Diplomatic and Consular Activities.**

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomats or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 28**Entry into Force**

Each of the Contracting States shall notify to the other completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the later of the notifications is given;
- (b) in Indonesia, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the later of the notifications is given.

ARTICLE 29**Termination**

This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirteenth of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Agreement shall cease to have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the 1st day of April next following the calendar year in which the notice is given;
- (b) in Indonesia, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the 1st day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

JN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

DONE in duplicate at Jakarta this Seventh day of August one thousand nine hundred and eighty seven in Hindi, Bahasa Indonesia and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**For the Government of
the Republic of India**

Sd/-

(VINOD C. KHANNA)

Ambassador of India

**For the Government of
the Republic of Indonesia**

sd/-

(RUSLI NOOR)

Director General for Foreign
Economic Relations

Protocol

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Indonesia, having entered into an Agreement for the avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed, at the time of signing the said Agreement, on the following provisions which shall constitute an integral part thereof :

1. For purpose of article 7 where a company which is a resident of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State, the profits attributable to the permanent establishment may be subjected to an additional tax in that other State in accordance with its law, but the additional tax so charged shall not exceed 10% of the amount of such profits after deducting therefrom income tax and other taxes on income imposed thereon in that other Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not affect the provisions contained in any production sharing contracts and contracts of work (or any other similar contracts) relating to oil and gas sector or other mining sector negotiated and concluded by the Government of Indonesia, its instrumentality, its relevant state oil and gas company or any other entity thereof before the first day of January 1984, with a person who is resident of India.

3. The provisions of paragraph 2 of article 11 shall also apply to interest arising to a branch of

a resident of a Contracting State in any third Country.

4 Notwithstanding the provisions of article 24, the provisions of this Agreement shall not be construed to restrict in any manner any exclusion, exemption, deduction, credit, or other allowance now or hereafter accorded:

- (a) by the laws of one of the Contracting States in the determination of the tax imposed by that Contracting State, or
- (b) by any other special arrangement on taxation in connection with the economic or technical cooperation between the two Contracting States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at JAKARTA this Seventh day of August one thousand nine hundred and eighty seven in Hindi, Bahasa Indonesia and English

languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail

For the Government of
the Republic of India

Sd/

(VINOD C. KHANNA) For the Government of
Ambassador of India the Republic of Indonesia

Sd -

(RUSLI NOOR)

Director General of Foreign
Economic Relations

[No 7747/F No 11] 30/69-L FD]

P. K. APPACHOO Ji Secy.